Established: 2023

BUNDELKHAND RESEARCH JOURNAL (BRJ)
(An Interdisciplinary, Open Access, Biannual, Multilingual and Peer-Reviewed e-Journal)
Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur, (Madhya Pradesh) India
(A State Government University)
2025, Vol. 3, Issue 2
Website: https://brj.mcbu.ac.in/

ISSN: 2584-0533

छतरपुर जिले में कृषि उपज के वित्तीयन एवं विपणन के आधुनिक माध्यमों का अध्ययन

संजय जैन एवं अशोक निगम

वाणिज्य अध्ययन शाला एवं शोध केन्द्र, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यलय छतरपुर (म.प्र)

ARTICLE INFO

Paper ID

BRJFLCM25255684

Corresponding Author

Sanjay Jain

Email

pj958602@gmail.com

DOI

https://doi.org/10.65554/brj.v3i2.02

Received: 24-07-2025

Revised:

Accepted: 03-11-2025

Published: 31-12-2025

ABSTRACT

यह शोध छतरपुर जिले में कृषि उपज के वित्तीयन एवं विपणन की आधुनिक साधनों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। जिले में परंपरागत वित्तीय साधनों में महाजन, सहकारी समितियाँ एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आधुनिक वित्तीय साधनों में किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना एवं डिजिटल ऋण प्रणाली शामिल हैं।विपणन प्रणाली में भी बदलाव देखा गया है; जहां पहले किसान मंडियों में दलालों के माध्यम से उपज बेचते थे, अब ई-नाम पोर्टल, किसान उत्पादक संगठन (FPO), कोल्ड स्टोरेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधे बाजार तक पहुंच रहे हैं।अध्ययन में पाया गया कि आधुनिक प्रणालियाँ किसानों की आय में वृद्धि, जोखिम में कमी और बाजार से सीधे जुड़ाव सुनिश्चित कर रही हैं। बावजूद इसके, डिजिटल साक्षरता की कमी, अवसंरचना की सीमाएँ और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अत: वित्तीय एवं विपणन प्रणाली को अधिक सुलभ, पारदर्शी और किसान-केंद्रित बनाने की आवश्यकता है।

Keywords: कृषि उपज, वित्तीय साधन, कृषि विपणन, कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

प्रस्तावना

छतरपुर जिला, बुंदेलखंड अंचल का प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः फसली उत्पादन, पशुपालन तथा कृषि आधारित गतिविधियों से संचालित होती है। प्रमुख खरीफ फसलें - सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूँगफली तथा तिलहन हैं, वहीं रबी में गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों प्रमुख रूप से बोई जाती हैं। कृषि यहाँ केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग भी है। कृषकों में से अधिकांश कृषक वर्ग के पास

स्वयं की इतनी पूँजी नही है, कि वह पूर्ण विनियोग कर सकें। अत: सरकार द्वारा कृषकों को आर्थिक रूप से सुदढ़ एवं कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से वित्तीय सुविधाये उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें सेवा सहकारी समिति एवं राष्टीय कृषि विकास बैंक और ग्रामीण विकास बैंक की मुख्य भूमिका है। देश के आर्थिक विकास में कृषि का विशेष योगदान है। और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कृषि के क्षेत्र में नवीन परिर्वतन हुए है। लेकिन वर्तमान समय में कृषि कार्य के लिए मुख्य समस्या पर्याप्त वित्त उपलब्ध ना होना एवं उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण कृषकों को आर्थिक हानि की समस्या उत्पन्न होती है। और वह लिए गये कृषि ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि नही कर पाने के कारण उन कृषकों को बैकों के द्वारा डिफाल्टर कृषक के रूप में सूचीवृद्ध कर उन्हें सेवा सहकारी समिति के लाभो से वंचित रखा जाता है। जिससे कृषक कृषि कार्य हेतु वित्तीय आवयश्कताओं की पूर्ति के लिए अन्य वित्तीय साधन के रूप में पारंपरिक वित्तीय स्त्रोत जैसे- साहूकार, रिश्तेदार, जमींदारों से ऊँची दरों पर कृषि कार्य के लिए ऋण लेते है। और समान्य दर की तुलना में अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते है। और उस ऋण का भुगतान नही कर पाने से किसान मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते है। किसानों द्वारा कृषि ऋण भुगतान नहीं कर पाने का मुख्य कारण यह भी है, कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाना है। जिसके कारण वह कर्ज के दलदल में फसते जा रहे है और किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है। इसलिए किसानो को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक वित्तीय स्त्रोत जैसे- सहकारी समितियॉ, ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी योजनाएँ और अनुदान आदि एवं नवीन वित्तीय योजनाऐं जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डिजिटल कृषि मिशन, कृषि अवसंरचना निधि आदि योजनाओं का लाभ लेकर कृषि कार्य के लिए पर्याप्त वित्त का प्रबंध किया जा सकता है। विपणन व्यवस्था में भी बदलाव देख्ने को मिले हैं। पहले किसान मंडी में बिचौलियों के माध्यम से उपज जाते थे, किंतु अब ई-नाम पोर्टल, किसान उत्पादक संगठन(FPOs), कोल्ड स्टोरेज, और Direct to consumer(D2C), जैसे नवाचारों ने किसानों को सीधे उपभोक्ताओं मक पहुंच प्रदान की है। नयागांव किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड राजनगर , बक्सवाहा किसान संगठन इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो किसानों को मंडी दर से बेहतर मूल्य दिलवाने में सहायक बन रहे हैं। छतरपुर जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र में कृषि मुख्यतः वर्षा

आधारित है। जहाँ जल संरचनाओं की कमी, सीमांत भूमि जोत और सीमित संसाधनों के कारण कृषकों को निरंतर वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में पारंपरिक सहकारी संस्थाओं और आधुनिक डिजिटल उपायों के सम्मिलित उपयोग की बड़ी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों के डिजिटलीकरण और ई-नाम पोर्टल से जोड़ने की पहल, तथा म.प्र. कृषि नीति 2020 में कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि छतरपुर जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र में कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके। इस शोध का मुख्य उद्देश्य छतरपुर जिले में कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त पारंपरिक एवं आधुनिक वित्तीय तथा विपणन प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए उनके प्रभावों, संभावनाओं और चुनौतियों को रेखांकित करना है, जिससे नीति-निर्माताओं, योजनाकारों तथा कृषकों के लिए ठोस दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जा सकें।

सोध साहित्य का पुनरावलोकन

1. देवेंद्र कुमार साहू (2013). शोध से पता चला कि सहकारी बैंकों ने पिछड़े कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु ऋण वितरण में भेदभाव तथा कृषि ऋण का अन्य उद्देश्यों में उपयोग करने से किसानों की आर्थिक स्थिति अपेक्षित सुधार प्राप्त नहीं कर सकी।

2. राकेश शर्मा (2018) के अनुसार, मध्यप्रदेश की 72 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं कृषि-आधारित उद्योगों पर निर्भर करती है, जिसके कारण इसे "हृदय प्रदेश" कहा जाता है।

3. अनिल मिश्रा एवं सुनीता गुप्ता (2020) ने अपने अध्ययन में बताया कि राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ विविध फसल उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। साथ ही पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन जैसे उपक्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं।

4. महेश वर्मा (2021) ने यह निष्कर्ष निकाला कि कृषि क्षेत्र का योगदान न केवल सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्रामीण जीवन-स्तर को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

5. निशा अग्रवाल (2023) के अध्ययन में यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कृषि योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एवं ई-नाम पोर्टल, कृषि विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

6. सोनी अरूण कुमार (2025) के अध्ययन में यह पाया गया कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुआयामी है। केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे उपक्षेत्र भी

राज्य की जीडीपी, ग्रामीण रोजगार और आय वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएँ तथा आधुनिक तकनीकें कृषि क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में नई संभावनाएँ खोल रही हैं।

7. मालवीय, वी. (2025). अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि जैविक कृषि की सफलता में सरकारी नीतियाँ, किसानों का ज्ञान और बाजार पहुँच की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यदि अनुकूल नीतियाँ, प्रशिक्षण और मजबूत बाजार जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए तो जैविक खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।

शोध का उद्देश्य

1. छतरपुर जिले में कृषि उपज के वित्तीय साधनों की मूल्यांकन करना।
2. आधुनिक विपणन साधनों की स्थिति और प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. किसानों की भागीदारी और लाभप्राप्ति की स्थिति जानना।
4. विपणन एवं वित्तीय चुनौतियो की पहचान एवं समाधान निकाना ।

शोध की पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण प्रमुख अनुसंधान पद्धति के रूप में किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और आँकड़ों का व्यवस्थित संकलन कर उनका तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। द्वितीयक आँकड़े मुख्य रूप से सरकारी रिपोर्टों (भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के कृषि एवं सहकारिता विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि विभागीय आँकड़े), सहकारी समितियों एवं बैंकों के वार्षिक आँकड़े (जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक), ई-नाम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड की रिपोर्टें, तथा NABARD, NCDC, FAO, ICAR जैसी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशनों से लिए गए हैं। इन आँकड़ों के माध्यम से जिले में कृषि वित्तीयन एवं विपणन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों, आधुनिक साधनों की उपलब्धता, उनके प्रभाव तथा किसानों की भागीदारी की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। प्राप्त आँकड़ों को वर्गीकृत, सारणीकृत एवं आवश्यकतानुसार आरेखों द्वारा प्रस्तुत कर अध्ययन को अधिक स्पष्ट, तुलनात्मक एवं व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है।

छतरपुर जिले में कृषि वित्तीयन की आधुनिक साधन

छतरपुर जिले में किसानों की वित्तीय सशक्तता और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न आधुनिक वित्तीय साधनों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। सहकारी समितियाँ और बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री

किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक ऋण और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण और अन्य कृषि कार्यों के लिए आसान और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है, जबकि PM-KISAN योजना सीधे लाभ अंतरण (DBT) के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त, डिजिटलीकरण ने वित्तीय सेवाओं की पहुँच को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया है, जैसे मोबाइल बैंकिंग और DBT के माध्यम से सब्सिडी और योजना लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुँचते हैं। छोटे और मध्यम किसानों के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ और किसान उत्पादक संगठन (FPO) आधारित ऋण भी उपलब्ध हैं, जो उपकरण, बीज और उर्वरक जैसी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इन आधुनिक वित्तीय साधनों के परिणामस्वरूप छतरपुर जिले के किसानों को परंपरागत ऋण संरचना की तुलना में अधिक सुविधा, योजना आधारित निवेश की संभावनाएँ और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है।

1. किसान क्रेडिट कार्ड: छतरपुर जिले में सहकारी समितियाँ एवं बैंक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जो प्रायः न्यून ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड सबसे प्रमुख साधन है, जिसके माध्यम से किसानों को अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध होता है। यह सुविधा बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई व अन्य कृषि कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष नकद सहायता दी जाती है, जिससे उनके दैनिक कृषि व्यय को पूरा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।डिजिटल बैंकिग: UPI, मोबाइल बैंकिग, नेट बैकिग, आधार लिंक बैकिग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का उपयोग किसी भी क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता था।

2. सहकारी समितियॉ: छतरपुर जिले में सहकारी समितियाँ कृषि वित्तीयन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जा सकती हैं। ये समितियाँ किसानों को कृषि ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण तथा उपभोक्ता वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के शोषण से बचाना तथा उन्हें सामूहिक शक्ति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस योजना के तहत पात्र किसानो को सालाना 6,000रू की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है।

3. नाबार्ड: छतरपुर जिले में नाबार्ड की योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। ग्रामीण सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को उत्पादन लागत घटाने व विपणन सुविधाएँ प्राप्त करने में मदद मिली है। SHG और FPO के माध्यम से सामूहिक शक्ति विकसित हुई है, जिससे किसान सीधे बाज़ार तक पहुँच पा रहे हैं। हालाँकि, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता की कमी, डिजिटल साक्षरता की न्यूनता और स्थानीय संस्थाओं पर निर्भरता जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। इसके बावजूद नाबार्ड को छतरपुर जिले की कृषि वित्तीय संरचना माना का सबसे सशक्त आधार स्तंभ जाता है। यह बैंक सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, लेकिन सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि वित्त की सुविधा देता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभार्थी किसान	वितरण की राशि (लाख)	औसत प्रति किसान (₹)
1	KCC	25,000	12,500	50,000
2	PM-KISAN	60,000	3,600	6,000
3	नाबार्ड सहायता	5,000 (अप्रत्यक्ष)	2,000	-

तालिका क्र.1

छतरपुर जिले मे वित्तीय योजनाओं का वार्षिक वितरण

स्रोत: NABARD रिपोर्ट 2023-24, जिला कृषि कार्यालय

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि छतरपुर जिले में कृषि वित्तीय योजनाओं का वितरण योजनाओं और लाभार्थियों के बीच काफी भिन्नता दर्शाता है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 25,000 किसानों को लाभान्वित किया गया, जिसमें प्रति किसान औसत राशि 50,000 रुपये रही, जो इसे बड़े ऋण और कृषि निवेश पर केंद्रित योजना बनाती है। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के माध्यम से 60,000 किसानों को लाभ मिला, लेकिन प्रति किसान औसत राशि केवल 6,000 रुपये रही, जो आय समर्थन पर अधिक केंद्रित है। NABARD सहायता योजना अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,000 किसानों तक सीमित रही और औसत राशि उपलब्ध नहीं है, जो इसे अधिक लक्षित और सहायक योजना बनाती है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या, वितरण राशि और प्रति किसान औसत में स्पष्ट भिन्नताएँ हैं, जो राज्य में कृषि वित्तीयन की विविधता और लक्षित प्रभाव को उजागर करती हैं। साथ ही, यह संकेत मिलता है कि छोटे और सीमांत किसानों तक पर्याप्त वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, जिसे आगे के अध्ययन और नीतिगत सुधारों में प्राथमिकता दी जा सकती है।

छतरपुर जिले में कृषि उपज विपणन के आधुनिक साधन

ई-नाम पोर्टल: e-NAM (Electronic National Agriculture Market): यह एक ऑनलाइन व्यापार प्लेट्फार्म है जो भारतीय कृषि मंडीयों को एकीकृत करने हेतु 14 अप्रैल 2016 केन्दीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। यह प्लेटफार्म किसानों, व्यापारियों और खरीददारों को एक साझा राष्ट्रीय बाजार प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्धेश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य एवं बिचौलियों की भूमिका को कम करना है। किसान, व्यापारी और क्रेता को सीधा संपर्क देना है। लगभग 1000 से अधिक APMC मंडियॉ ई-नाम से जुड़ चुकी है।

1. किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना।
2. बोली प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, जिससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आती है।
3. गुणवत्तानुसार ग्रेडिंग और प्रमाणन की सुविधा।
4. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की व्यवस्था, जिससे किसानों को समय पर भुगतान प्राप्त हो सके।
5. राज्यों की विभिन्न कृषि मंडियों को आपस में जोड़कर **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार** का निर्माण।

फसल का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अनुमानित उत्पादन (टन)	MSP2023-24 (रू/क्विंटल)	MSP2024-25 (₹/क्विंटल)	MSP में परिवर्तन	MSP में परिवर्तन प्रतिशत में
खरीब की फसलें						
सोयाबीन	1,10,000	1,60,000	4600	4892	292	6.3 %
धान (सामान्य)	50,000	20,000	2183	2300	117	5.4 %
मक्का	10,000	20,000	2090	2225	135	6.5 %
मूंग	25,000	32,000	8558	8682	124	1.4 %
उड़द	35,000	45,000	6950	7400	450	6.5 %
मूंगफली	5,000	15,000	6377	6783	406	6.4 %
अरहर	20,000	28,000	7000	7550	550	7.9 %
रबी की फसलें						
गेहूं	1,20,000	3,60,000	2275	2425	150	6.6 %
चना	90,000	1,35,000	5440	5650	210	3.9 %
सरसों	25,000	30,000	5650	5950	300	5.3 %
मसूर	18,000	22,000	6425	6700	275	4.3 %

तालिका क्र. 2

छतरपुर जिल की प्रमुख फसले: क्षेत्रफल, उत्पादन और MSP

जिला कृषि कार्यालय, जिला सांख्यिकीय कार्यालय

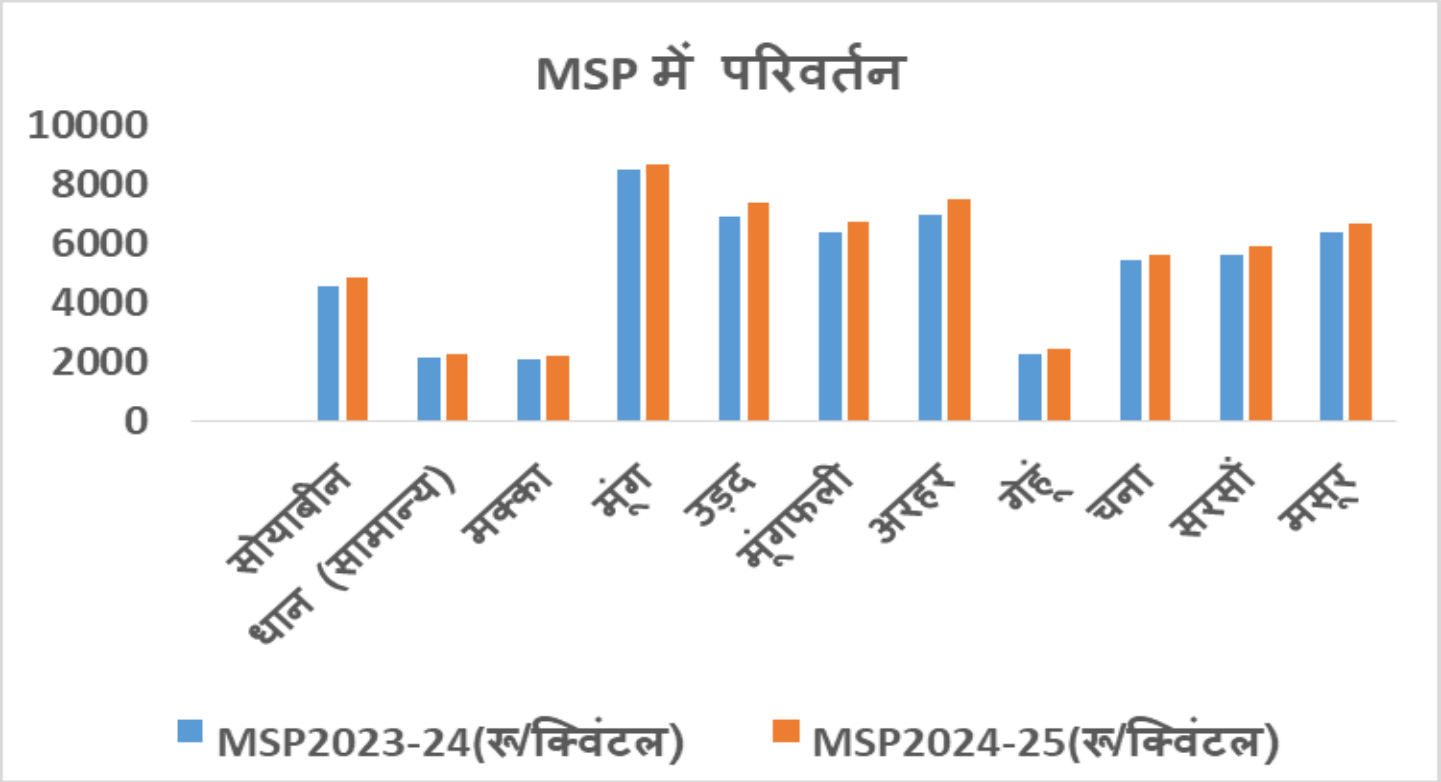

ग्राफ क्र.1

MSP मूल्य 2023-24 एवं 2024-25 में हुए परिर्वतन

FPOs (Farmer Producer Organization): किसान उत्पादक संगठन एक सरकारी संस्था है, जिसमें स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। कम से कम 10 किसान सदस्य होते हैं । इनका उद्धेश्य किसानों को एकजुट करके उन्हें संगठित, आत्मनिर्भर और सक्त बनाना है जिससे वे कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण विपणन और मूल्यवर्धन के क्षेत्रों में बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। छतरपुर जिले में किसान उत्पादक संगठन (FPOs) निम्न है-

1. नयागांव किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड: इसकी स्थापना राजनगर विकासखंड में की गई है। इसेमें कुल सदस्य 400 किसान है। जो गेहूँ, चना, सरसों के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति के लिए बनाया गया है।

2. बक्सवाहा किसान उत्पादक संगठन: इस संगठन की स्थापना बक्सवाहा तहसील में भारतीसय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। मुख्य फसल मूंगफली, मसूर, तिलहन और जैविक खेती को बढावा देना तथा यह ई-नाम और जिला मंडी से सीधे संपर्क में रहती है।

सीधे उपभोक्ता तक: D2C (Direct to consumer): यानी "सीधे उपभोक्ता तक" यह एक व्यापार का नया मॉडल है जिसमें उत्पादक अपने उत्पाद को सीधे ग्राहक तक पहुचाता है जिससे बिचौलियों (जैसे- थोक विकेता, वितरक, रिटेल) की मध्यस्था नही रहती है। इसमें उत्पादक अपनी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या खुद के स्टोर्स से ग्राहकों को सीधे बेचा जाता है।

कोल्ड स्टोरेज एवं गोदाम: जिले में 2 कोल्ड स्टोरेज एवं 68 वेयार हाउस है। यह एक ऐसा भंडारण केंद्र होता है, जहाँ तापमान को

नियंत्रित किया जाता है, ताकि शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक स्टोरेज किया जा सके। जैसे- फल, सब्जी, फूल, दूध, आदि की ताजगी बनाए रखने तथा बर्बादी को रोकने एवं कृषि उत्पादो को बाजार के अनुकूल सयम तक संगहित रखने में मद्द करते है ।

प्राइवेट एग्रीटेक प्लेटफार्म: यह निजि क्षेत्र में विकसित तकनीकी प्लेटफार्म है। जो किसानों, कृषि व्यवसायियों और आपूर्तिकर्ता के अन्य हितधारकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका उद्धेश्य कृषि को अधिक स्मार्ट, कुशल, लाभकारी बनाना होता है।

क्र.	योजना का नाम	उद्धेश्य	लाभार्थी वर्ग	प्रमुख विशेषताएँ
1	राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)	मंडियो को डिजिटलीकरण	किसान, व्यापारी	पारदर्शी ऑनलाइन बोली, बेहतर मूल्य
2	किसान उत्पादक संगठन (FPO)	किसान संगठनों का सशक्त करना	पंजीकृत किसान का संगठन	15 लाख तक अनुदान कार्यशी पूंजी, प्रशिक्षण
3	मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (MP-Govt.)	किसानों की आय में वृद्धि	राज्य के सभी किसान	केंन्द्र की PM-Kisan योजना की पूरक
4	कृषि अवसंरचना निधि (AIF)	भंडारण,कोल्डस्टोरेज निर्माण	निजि,सहकारी	₹3 ब्याज अनुदान, ₹ 2 करोड़ तक ऋण
5	मूल्य समर्थन योजना (MSP scheme)	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद	MS योग्य किसान	घोषित दर पर फसल क्रय, मंडी में सरकारी खरीद

तालिका क्रमांक 3

कृषि विपणन एवं वितरण से संबंधित योजनाएँ

स्रोत: NABARD रिपोर्ट 2023-24, जिला कृषि कार्यालय, जिला सांख्यिकीय कार्यालय

तालिका क्रमांक 3 छतरपुर जिले में लागू प्रमुख कृषि योजनाएँ जैसे e-NAM, FPOs, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, कृषि अवसंरचना निधि (AIF) और MSP योजना किसानों की वित्तीय सशक्तता और विपणन में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हुई हैं। e-NAM प्लेटफॉर्म ने मंडियों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से मूल्य पारदर्शिता बढ़ाई और बिचौलियों पर निर्भरता घटाई है, जबकि FPOs (किसान उत्पादक संगठन) छोटे और मध्यम किसानों को सामूहिक विपणन, उपकरण साझा करने और प्रशिक्षण के माध्यम से

विपणन और प्रबंधन क्षमता में सुधार प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और PM-Kisan योजना ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए किसानों की आय स्थिर करने में योगदान दिया है, वहीं कृषि अवसंरचना निधि (AIF) ने कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस जैसी भंडारण सुविधाओं का विकास कर फसल की गुणवत्ता और सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित की है। MSP योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिला है, जिससे बाजार में मूल्य अस्थिरता के प्रभाव कम हुए हैं। संक्षेप में, ये आधुनिक योजनाएँ छतरपुर जिले में किसानों की आय बढ़ाने, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और विपणन सुधार में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, हालांकि उनका पूर्ण प्रभाव डिजिटल साक्षरता, अवसंरचना और स्थानीय मध्यस्थों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

प्रमुख समस्याएँ

1. किसानों की डिजिटल साक्षरता की कमी: अधिकांश किसान ई-नाम, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते।

2. ग्रामीण अवसंरचना का अभाव: खराब सड़कें, अनियमित बिजली आपूर्ति और सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी कृषि उपज के त्वरित और सुरक्षित परिवहन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

3. कोल्ड-चेन और वेयरहाउसिंग की अपर्याप्तता: भंडारण और फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कोल्ड-स्टोरेज और वेयरहाउस सुविधाओं का अभाव है।

4. मध्यस्थों का प्रभुत्व: परंपरागत मंडियों में बिचौलियों का अधिक नियंत्रण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधित करता है।

समाधान एवं सुझाव

1. ई-नाम का पूर्ण डिजिटलीकरण: जिले की सभी मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़कर किसानों को सीधे ऑनलाइन नीलामी और पारदर्शी मूल्य निर्धारण का लाभ दिलाया जाए।

2. अधिक FPOs की स्थापना और प्रशिक्षण: किसानों के लिए अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPOs) स्थापित किए जाएँ और उन्हें विपणन, वित्तीय प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण दिए जाएँ।

3. वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज निर्माण: सरकारी और निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से जिले में पर्याप्त वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण किया जाए ताकि उपज की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में सुधार हो।

4. डिजिटल बैंकिंग और माइक्रोफाइनेंस की आसान पहुँच: किसानों को मोबाइल बैंकिंग, KCC, माइक्रोफाइनेंस और अन्य वित्तीय

योजनाओं तक आसान पहुँच प्रदान की जाए ताकि निवेश और ऋण प्राप्ति सरल और समयोचित हो।

5. किसानों में विपणन एवं वित्तीय साक्षरता का प्रसार: किसानों को मार्केटिंग रणनीतियों, मूल्य वर्धन, ऋण प्रबंधन और डिजिटल वित्तीय उपकरणों के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाए, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्थिरता बढ़ सके।

निष्कर्ष

छतरपुर जिले में कृषि उपज के वित्तीयन एवं वितरण की प्रणली में आधुनिक वृत्तियॉ धीरे-किसानों की स्थिति में सुधार देखा गया है, परंतु इसके व्यापक लाभ के लिए प्रशिक्षण, संरचना और नीति-निर्माण स्तर पर और प्रयास आवश्यक हैं।

जिले की कृषि व्यवस्था में परंपरागत वित्तीय स्त्रोत जैसे महाजन, सहकारी समितियॉ एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ अभी भी ग्रामीण किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, किंतु हाल के वर्षों में आधुनिक वित्तीय उपायों जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डिजिटल बैकिंग, तथा नबार्ड जैसी आधुनिक वित्तीय व्यवस्थाओं ने किसानों को सुल्भ और पारदर्शी ऋण सुविधा प्रदान की है। वहीं वितरण प्रणाली में ई-नाम पोर्टल, किसाना उत्पादक संगठन (FPO), D2C (Direct to Consumer), कोल्ड स्टोरेज, मॉडल और निजि एग्राटेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसान सीधे बाजार तक पहुँचनें में सक्षम हो रहे है, जिससे उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। और बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है। यह आधुनिक प्रणाली किसानों की आय वृद्धि, जोखिम प्रबंधन और बाजार से सीधा जुडाव सुनिश्चित कर रही है। हालांकि डिजिटल साक्षरता की कमी, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव तथा अधोसंरचना की अपर्याप्तता जैसे मुद्दे अब भी सामने आते है, जिनका समाधान आवश्यक है समग्र रूप से कहॉ जा सकता है, कि छतरपुर जिले में यदि इन चुनौतियों को दूर कर वित्तीय एवं विपणन प्रणाली को अधिक किसान हितैषी बनाया जाए। जिससे किसानों को यह न केवल किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि जोखिम भी कम कर रही है, बिचौलियों की भूमिका में स्पष्ट कमी देखी जा रही है। जिससे किसान आधुनिक कृषि व्यवस्था का पूर्ण लाभ उठाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते।

सन्दर्भ-सूची

1. अग्रवाल निशा (2003) मध्यप्रदेश में कृषि योजनाओं का प्रभाव: एक विश्लेषण। (शोध प्रबंध में संलग्न शोध-पत्र)
2. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय https://agrocoop.nic.in

3. FAO. (2021). Digital Agriculture: Farmers in the Age of Data. Retrieved from https://www.fao.org/
4. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन (2004)
5. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. (2023). e-NAM progress report 2022–23. Government of India. https://enam.gov.in
6. मालवीय, वी. (2025) मध्य प्रदेश में जैविक कृषि की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।(शोध-पत्र)
7. मिश्रा, अनिल एवं सुनीता गुप्ता (2020) मध्यप्रदेश की कृषि: विविधता एवं ग्रामीण अर्थव्यस्था पर प्रभाव। (शोध प्रबंध में संलग्न शोध-पत्र)
8. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2024). Annual report 2023–24. https://www.nabard.org/
9. शर्मा, राकेश (2018) मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान।(शोध-पत्र)
10. साहू, देवेंद्र कुमार. (2013) इंदौर एवं धार जिले के केंद्रीय जिला सहकारी बैंक का कृषि विकास में योजनाओं में विश्लेषणात्मक अध्ययन।
11. सोनी, अरूण कुमार (2025) कृषि क्षेत्र के विकास में म.प्र. शासन का योगदान।(शोध पत्र)
12. वर्मा, महेश (2021) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान।(शोध-पत्र)